

घसाबारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्डं 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित



सं० 2.62]

नई बिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 1976/श्रावण 8, 1898

No. 262]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 1976/SRAVANA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July 1976

- G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporation Rules, 1965, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 1976.
 - (2) They shall be deemed to have come into force on 1st day of January, 1973.
- 2. In the Food Corporations Rules, 1965, in rule 11 in sub-rule (2), for the figures "1800-100-2000", the figures "1800-100-2000-125/2-2250" shall be substituted.

Explanatory Memorandum

The Food Corporations (Amendment) Rules, 1976 have been made to implement the decisions taken by the Central Government on the proposals of the Food Corporation of India regarding revision of pay scales and conditions of service of the employees of the Corporation based on the recommendations of the Pay Committee constituted by the Corporation for this purpose. The Committee had recommended revision of pay scales of all employees of the Corporation including its Secretary, with effect from the 1st January, 1973 on the analogy of the revision of pay scales in the Central Government. The Central Government accepted the proposal of the Food Corporation to give effect to revision of pay scales with effect from the 1st January, 1975 in order to give greater benefit to its employees.

[No. F. 2-1/76-FC-1.]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि झौर सिचाई मंत्रालय

(साध विभाग)

मधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1976

सा॰ का॰ कि॰ 491 (म).——केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम म्रिधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य निगम नियम, 1965 में भौर संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, मर्थात् :——

- 1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1976 है।
 - (2) ये 1 जनवरी, 1973 को प्रवृत्त हुए समझे आयेगे।
- 2. खाद्य निगम नियम, 1965 में, नियम 11 के उपनियम (2) मे, श्रंक "1800~100~ 2000" के स्थान पर "1800~100~ 2000—125/2~2250" रखे जायेंगे।

स्पष्ठीकारक ज्ञापन

खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 1976 उन विनिष्टचयों की क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए हैं जो केन्द्रीय सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों और सेवा की शतों के पुन-रीक्षण के बारे में निगम की प्रस्थापनाओं की बाबत किए थे जो कि निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित बेतन समिति की सिफारिशों पर श्राधारित हैं। समिति ने केन्द्रीय सरकार के बेतनमानों के पुन-रीक्षण के सादृश्य पर, 1 जनवरी, 1973 से, निगम के सचिव सहित उसके सभी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण की पुनरीक्षण की सिफारिश की थी। केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1973 से बेतनमानों के पुनरीक्षण की प्रभावी करने की खाद्य निगम की प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया जिससे कि उसके कर्मचारियों की श्रीर श्रीक्षक फायदा दिया जा सक।

[सं॰ फा॰ 2-1/76-एफ॰ सी॰---I] एल॰ सी॰ गुप्त, संयक्त संख्वा।